International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 2, February- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक विकास

डॉ0 जगदीश चन्द्र भट्ट
सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण
(पौड़ी) उत्तराखण्ड

सरांश

समाज के निचले से निचले स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को वित्त की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया जो वित्तीय समावेशन होती है जिसमें लक्ष्यित वर्ग, श्रमिक वर्ग, भूमिहीन, ग्रामीण सीमान्त किसान तथा असंगठित मजदूर वर्ग आते है। अमर्त्य सेन तथा जीनड्रीज जैसे लोगो ने यह बताया कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर स्वतः रिसाव के द्वारा मानव कल्याण में सुधार सुनिश्चित करेगा और सरकार को अपनी आक्रामक व सकारात्मक आर्थिक राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों द्वारा आर्थिक वृद्धि से उत्पन्न परिणाम को लोगों तक पहुंचाना होगा। आर0बी0आई ने वित्तीय समावेशन की दिशा मे अनेक प्रयास किये है जैसे स्वाभिमान योजना का प्रारम्भ, कृषिको तथा कमजोर वर्ग को प्राइम लेंडिग की अनिवार्यता, मनरेगा मे खाते मे भुगतान आदि। हाल के समय में बैंकों द्वारा सीबीएस प्रणाली अपनाये जाने के पश्चात प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान NEFT/RTGS, मोबाइल बैंकिग, इन्टरनेट, आईएमपीएस आदि। इस माध्यम से वित्तीय संस्थाओं तक आसानी से पहुंच हो सकेगी तथा ग्राहकों, विनियामकों, और अर्थव्यवस्था के सभी वर्गो को लाभ मिलेगा।

संकेत शब्दः वित्तीय समावेशन; नकदरहित लेनदेन; कोर बैंकिंग।

1. प्रस्तावना

यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर सरकारें आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचाारिक माध्यम में शामिल करने का प्रयास करती है ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभ को प्राप्त कर सके तथा उसे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा मे लाया जा सके। जिसके परिणाम स्वरूप निचले तबके के व्यक्ति को भी बचत व निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सस्ती कीमत पर कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्गो को, उनकी आवश्यकतानुसार समय समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को ही वित्तीय समावेशन कहते है। समाज के निचले से निचले स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को वित्त की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया ही वित्तीय समावेशन है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय समावेशन का लक्ष्यित वर्ग जिसमें श्रमिक वर्ग, भूमिहीन, ग्रामीण सीमान्त किसान तथा असंगठित मजदूर वर्ग आते है। इन वर्गो के आर्थिक पुर्ननिर्माण के परिणाम स्वरूप ही देश का वास्तविक विकास सम्भव है।

Financial inclusion may be defined as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost.

जगदीश भगवती जैसे कुछ अर्थशास्त्री यह मानते है कि आर्थिक सवृद्धि दर स्वतः लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार या मानव कल्याण में उच्च वृद्धि में रूपान्तरित हो जाता है । वहीं अमर्त्य सेन तथा जीनड्रीज जैसे लोग यह मानते है कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर स्वतः रिसाव के द्वारा मानव कल्याण में सुधार सुनिश्चित करेगा और सरकार को अपनी आक्रामक आर्थिक राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों द्वारा आर्थिक वृद्धि से उत्पन्न परिणाम को लोगों तक पहुंचाना होगा।

आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ना जिससे सबका समान विकास हो सके, कोई भी वर्ग छूट न जाये निश्चित रूप से समावेशी विकास कहलायेगा। आर्थिक समीक्षा 2012–13 में यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक विकास मे वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक समावेशन भी सम्मिलित है और प्रायः सामाजिक समावेशन से वंचित लोग

ही वित्तीय समावेशन से भी वंचित है। इस प्रकार समाज का एक बड़ा भाग जो उपेक्षित व वित्तीय सेवाओं से वंचित है उसको वित्तीय सीमा मे लाये बिना आर्थिक विकास नही प्राप्त किया जा सकता है।
जनगणना 2011 के अनुसार देश की 59 प्रशित परिवारो को ही बैकिंग सुविधा प्राप्त है। इसीलिए निर्धनता के कुचक्र को अभी तक तोड़ा नही जा सका है। पर वर्तमान मे सरकार वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता के माध्यम से विकास की ओर बढ़ रही है।

विश्व बैंक के अनुसार लगभग 02 अरब विश्व की जनसंख्या औपाचारिक रूप से वित्तीय सेवाओ का उपयोग नही करती है और सर्वाधिक गरीब परिवारों मे 50 प्रतिशत से ज्यादा व्यस्क अभी भी बैंकरहित है।

1.1- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य विकास की मुख्य धारा से छूटे हुए लोगो को बैंकिंग सेवाए प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इन वर्गो को सेठ, साहूकारो, स्वर्णकारों के चंगुल से छुड़ा कर वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक इनकी पहुंच बनाकर विकास की मुख्य धारा मे जोडना है। जिससे देश समग्र रूप से विकास कर सके और इस विकास का सभी वर्गो को अनुभव प्राप्त हो।

वर्ष 1969 जहॉ से बैंको के राष्ट्रीयकरण की प्रकिया शुरु हुई, वित्तीय समावेशन के प्रारम्भिक अवस्था के रूप में इसे हम जानते है जब 14 बड़े व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 और बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। न्यु बैंक आफ इंडिया का पीएनबी में विलय हो जाने के कारण इनकी सं0 कुल 19 रह गयी पर 2008 में आईडीबीआई का राष्ट्रीयकरण होने (स्रोत–भारत 2008)के कारण वर्तमान में इनकी सं0 कुल 20 है।

1.2 वित्तीय समावेशन के कारक

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वित्तीय समावेशन किस प्रकार हो तथा इसका सबसे प्रभावी मॉडल क्या हो जिससे लोग आसानी से जुड़ सके। आर0बी0आई ने वित्तीय समावेशन की दिशा मे अनेक प्रयास किये है जैसे स्वाभिमान योजना का प्रारम्भ, कृषिको तथा कमजोर वर्ग को प्राइम लेंडिग की अनिवार्यता, मनरेगा मे खाते मे भुगतान आदि।

सरकार इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण तरीको का प्रयोग कर रही है जो निम्नवत है–

1. अधिक से अधिक संख्या में बैंकिग शाखाओं की स्थापना।
2. अधिक से अधिक संख्या में No Frill Account खोलने पर जोर देना।
3. अधिक संख्या में सामान्य क्रेडिट कार्डो, डेबिट कार्डों तथा किसान क्रेडिट कार्डो का निर्गमन तथा भीम ऐप की शुरूआत।
4. आई सी बेस खाते–कोर बैंकिग समाधान से सम्बद्ध एक सशक्त बैंकिग नेटवर्क।
5. वित्तीय साक्षरता का विस्तार–स्वर्ण मौद्रिकरण योजना का प्रारम्भ।
6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा अटल पेंशन योजना का प्रारम्भ।
7. भुगतान बैंक और लघु बैंक की शुरूआत।
8. प्रधानमंत्री जनधन योजना।
9. डिजिटल इंडिया की शुरूआत
10. सुकन्या समृद्धि येाजना।

प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे 28 अगस्त 2014 को शून्य बैलेन्स के साथ शुरू किया गया, इस दिशा में शुरू की गयी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी योजना हैं। ग्राहक को इसमें एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें एक लाख का दुर्घटना बीमा कवर हैं। 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच खाता खुलवाने तथा योजना की पात्रता रखने सम्बन्धी शर्तो का पालन करने पर 30000 रुपये का जीवन बीमा कवर तथा 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा के रुप मे अनुमन्य हेागा। यह सुविघा परिवार के आयप्राप्तकर्ता सदस्य की मृत्यु तक सीमित होगी और केवल 5 वर्ष ही प्राप्त होगी। इसके अन्तर्गत खाता धारक को 3 वर्ष बाद 5000 रुपये का ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी जायेगीं। 23 अगस्त 2014 के सप्ताह में सर्वाधिक खाता खोलने के लिए इसी मिनी वर्ल्ड रिकार्ड में शमिल किया गया। अगस्त 2017 के मध्य तक इस स्कीम के अन्तर्गत 29.48 करोड़ खाते खोले गये जो एक बड़ी उपलब्धि है।

वित्तीय समावेशन के तीव्र विस्तार हेतु बैकिंग व नान–बैंकिग संस्थाओं की स्थापना में बृद्वि हुई है। यहां पर वर्ष 2015 तक 1400 से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की स्थापना हुई है। जो अधिकतर दूर–दराज के क्षेत्रों में कार्यरत है। हाल के समय में बैंकों द्धारा सीबीएस प्रणाली अपनाये जाने के पश्चात प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है

जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान NEFT/RTGS, मोबाइल बैंकिग, इन्टरनेट, आईएमपीएस आदि। आधार (Aadhaar) के प्रारम्भ होने के बाद आधार समर्थित उत्पाद जैसे खाता खोलने के लिए ई–केवाईसी, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), सूक्ष्म एटीएम, आधार से ग्राहक के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा आधार आधारित केन्द्रीयकृत ऋण आदि, आधार से पूरा वित्तीय परिदृष्य व प्रक्रिया परिवर्तित होगी और पात्र व्यक्ति ही वित्तीय समर्थन का लाभ प्राप्त कर पायेगा।

1.3 वित्तीय समावेशन बढाने के उपाय

1. मूल बचत जमा खाता खोलना, जिसमे शून्य बैलेन्स पर भी खाते खोलने की छूट।
2. के वाय सी को सरल किया जाना।
3. बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रो मे बैंको की स्थापना करने का निर्देश।
4. नये बैंको का लाइसेन्स देना।
5. मोबाइल बैकिंग पर जोर देना
6. वित्तीय साक्षरता अभियान पर बल दिया जाना।
7. आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना।

भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको को उच्चतम स्तर पर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करता है। और व्यापारिक बैंक भी इस दिशा मे आगे बढ़ रहे है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिर्पोट 27फरवरी 2018 के अनुसार देश में व्यापारिक बैंको की शाखाओ की अद्यतन स्थिति नीचे सारणी सं0–01 में इस प्रकार है–

सारणी सं0–01

व्यापारिक बैंक एक नजर में			
व्यापारिक बैंको की शाखाएं	**Dec-2017**	**Sep-2017**	**Jun-2017**
ग्रामीण क्षेत्र	49143	49022	48774
अर्ध – शहरी क्षेत्र	38281	38120	38230
शहरी क्षेत्र	25201	25067	25131
महानगरीय क्षेत्र	26850	26835	27105
समग्र	**139475**	**139044**	**139240**

गॉवो, शहरी, महानगरीय क्षेत्रो में निरन्तर बैंकिंग शाखाओ व बैंकिंग सुविधाओ में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल लेनदेन का वातावरण फैल रहा है।

1.4 वित्तीय समावेशन की माप :–CRISIL

रेटिंग एजेन्सी क्राइसिल ने वित्तीय समावेशन की माप हेतु एक सूचकांक विकसित किया है जिसे क्राइसिल इन्क्लुसिक्स कहते है । यह सूचकांक 0–100 के स्केल में तैयार किया गया सूचकांक ही यह तीन प्राचलों को शामिल करता हैं ।

1. ब्रान्च पैठ (Branch Penetration) बैकिंग सेवाओं के विस्तार को व्यक्त करती है।
2. साख पैठ (Credit Penetration) ऋणों के विस्तार को प्रदशित करने की विधि है।
3. जमा पैठ (Deposite Penetration) बचत जमाओ के विस्तार को प्रदर्शित करने की विधि है।

क्राइसिल बैंकिंग, बीमा, शाखा आदि चरों को समायोजित करके समावेशन की व्याख्या करता हैं ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में काइसिल इन्क्लूसिक्स स्कोर जहां 2009 में 35.4 था 2011 में बढ़कर 40.1 हेा गया। 2009–2010 के बीच देश के 618 जिलों मे वित्तीय समावेशन का विस्तार हुआ हैं। तीन ऐसे राज्य जो उच्च स्कोर में थे वे हैं पाडुचेरी, चडीगढ़ और केरल। इसके बारे मे कहा गया कि "Higher The score, "Higher the livel of Financial Inclusion" .

रिपोर्ट के अनुसार–

a) उच्च वित्तीय समावेशन सर्वाधिक उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,सिक्किम,केरल राज्यों में हुई है।

b) उच्च साख विस्तार का स्तर जिसमें उत्तराखण्ड का स्थान औसत से नीचे है।

c) उच्च जमा विस्तार का स्तर जिसमें उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडींगढ़, हरियाणा, दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल राज्य सर्वाधिक विस्तार किये है।

उपरोक्त के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल परिवर्तनीयता की ओर बढ़ रही हैं। जिसके प्रारूप इस प्रकार है–

1–ई–कुबेर (RBI का Core Banking Solution) से सम्बद्ध एक सशक्त बैंकिग नेटवर्क(1,15,000 शाखाएं) जिसका अब ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो रहा हैं।

2–भारतीय डाक (1,55,000 आउटलेट) डाकघर तथा टर्मिनलों की एक महत्वपूर्ण आउटरीच जो कि देशभर मे एक ताकतवर नकद जमा/नकद निकासी को सुगम बना सकती हैं।

3–886 मिलियन मोबाइल कनेक्शन तथा 72प्रतिशत मोबाइल पैठ के साथ देशव्यापी टेलीकॉम नेटवर्क की स्थापना।

4–मोबाइल फोनों द्वारा निधियों का तत्काल हस्तान्तरण।

5–विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पहचान प्रणाली (आधार) जिसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति कवर हो चुके हैं तथा इसमे वृद्धि की प्रक्रिया आगे जारी है।

1.5 वित्तीय समावेशन का प्रभाव

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जनधन योजना, मुद्रा लोन योजना, रूपे कार्ड का निर्गमन..... आदि यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए सबसे व्यापक सार्थक प्रयास किये जा रहे है। ये योजनाएं गरीबों की आजीविका में सुधार करने और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उपक्रमों के माध्यम से सहायता करने मे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। जी–20 में सियोल–2010 एमवाईएपी में वित्तीय समावेशन को विकास के नौ मुख्य स्तम्भों के रुप मे शामिल किया हैं। इस योजना का प्रभाव निश्चित रूप से ग्रामीणो के जीवन स्तर मे सुधार लायेगा और अर्थव्यवस्था के जीवन स्तर तथा रोजगार में वृद्धि होगी।

वित्तीय समावेशन यदि सही दिशा में क्रियाशीलन हो तो अर्थव्यवस्था पर भविष्य में निम्न प्रकार के प्रभाव पड़ सकते है जो इस प्रकार है–

1- इस कार्यक्रम में सभी गांवों के सभी परिवारों को समाविष्ट करनें का लक्ष्य रखा गया है। यद्यपि उद्देश्य सम्पूर्ण जनता को समाविष्ट करनें का है फिर भी, इस समावेशन में अन्त्योदय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गांव के प्रत्येक परिवार को वित्तीय सेवाएं दी जायेंगी।

2- गरीब वर्ग में गरीब महिलाओं, एससी/एसटी और जनजातीय कमजोर वर्ग को पहले प्राथमिकता दी जानी है।

3- Last mile connectivity सुनिश्चितता तथा व्यापार प्रतिनिधि जो स्थान – स्थान पर स्वयं जातें है एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध होंगे। जिससे जनता का उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा।

4- जनधन योजना, स्पष्ट लक्ष्य के साथ संचालित की जायेगी क्यों कि इसमें 1 लाख रुपये बीमें के साथ एक रूपे कार्ड भी दिया जायेगा अर्थात गरीबी उन्मूलन के अवसर सृजित किये जायेंगे।

5- इसे केन्द्र, राज्य और जिला स्तर तक बढ़ा दिया गया है और सभी खाते सीबीएस सिस्टम में खोले जायेंगे। रूपे कार्ड के माध्यम से परिचालित किये जायेंगे।

6- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया जायेगा जिसमें बैंको द्वारा साक्षरता अभियान, वित्तीय साक्षरता केन्द्र (Financial literacy centre FLC), अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में माह में कम से कम बार जागरुकता शिविर लगाकर वित्तीय साक्षरता दी जायेगी।

7- सभी को समावेशन में समान हिस्सेदारी की सुनिश्चितता दी जा रही है जिससे उपेक्षित वर्ग इस व्यवस्था में जुड़ सकेगा।

इस व्यवस्था के तीव्र प्रसार से लोगो की वित्तीय संस्थाओं तक आसानी से पहुंच तथा ग्राहकों, विनियामकों, और अर्थव्यवस्था के सभी वर्गो को लाभ मिलेगा। वित्तीय समावेशन के लिए यह आवश्यक है कि इसका प्रत्येक घरों तक पहुच स्थापित हो। देश का 90प्रतिशत श्रमिक वर्ग असंगठित क्षेत्र से आता है और इनकी बैंको तक सुलभ पहुंच होने से इस प्रक्रिया को मजबूती प्राप्त होगी। इसके लिए वित्तीय साक्षरता का होना भी अति आवश्यक है जिससे लोग आसानी से वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ सके तथा नकदरहित लेन–देन को प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही सरकार के विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमो को लक्ष्यित वर्ग तक पहुचाने मे आसानी होगी। आनलाइन बैकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आदि का उपयोग बढ़ेगा और लोग इस प्रकार के तकनीको को प्रयोग करने को प्रेरित होंगे जिससे लेन–देन की लागतो मे कमी आयेगी। पर इन सभी के लिए मजबूत टेलकाम नेटवर्क स्थापित करना होगा। इसके लिए सरकार, रिजर्व बैंक व अन्य बैंको को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा।

सन्दर्भ

1- लाल,एस0एन0 (जून 2016) भारतीय अर्थव्यवस्था–सर्वेक्षण व विश्लेषण, शिव पब्लिकेशनःइलाहाबाद।
2- सिंह, रमेश (आठवां संस्करण, 2016) भारतीय अर्थव्यवस्था, टाटा मैक्ग्रा हिल एजूकेशन पब्लिकेशन।
3- श्रीराम, एम0एस0 (दिसम्बर 2015) इनक्लूसिव फाइनेन्सियल इन्डिया रिर्पोट, सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4- सुन्दरम के0पी0एम0 एवं रुद्र दत्त(72वां संस्करण 2016)भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0चन्द लिमि0।
5- Nilkani Nandan, and Shah Viral, (2015) Rebooting India,Realizing a billion aspirations. Pub- London:Allen Lane.
6- Karmakar K.G. , Banergee G.D. and Mahapatra M.P.(2016)Towards Financial Inclusion in India, Sage Publication India, Pvt. Ltd.
7- अर्जुन सहाय. 01 सितम्बर 2017 उभरते भारत मे वित्तीय समावेशन, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार।
8- भारत सरकार (2008) ''वित्तीय समावेशन पर रिपोर्ट'' अध्यक्षः डॉ. सी. रंगराजन।
9- आर0बी0आई0 बुलेटिन 2014/फाइनेन्सियल इनक्लुयजन ःडी0सुब्बाराव ।
10- QUARTERLY STATISTICS ON DEPOSITS AND CREDIT OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, RBI Report 27February 2018